Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

# मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 R.N.I. No. 66400/97

यमुना–मुक्ति यात्रा : जन आन्दोलन बनाम सियासत 3

बेटा और बेटी एक समान क्यों नहीं है? 4

भारत बन्द के विरोधियों के जवाब में 6

वे कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी याद नहीं करते 7

वर्ष 26 अंक 9 फरीदाबाद, शनिवार, 16-31 मार्च 2013 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 2 रुपया

# एम्बुलेंस फ़ोन नं. 102 सेवा नहीं विज्ञापन बाजी

## बी. के अस्पताल को बूचड़खाना बनाये रखने की ठान रखी है सरकार ने

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** शहर की जनता को चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने हेतु करोड़ों की लागत से चलाया जा रहा हरियाणा सरकार का प्रमुख चिकित्सा केन्द्र बादशाह खान अस्पताल अपनी बूचड़खाने वाली छवि छोड़ने को तैयार नहीं। नई इमारत व चार गुणा डाक्टरों की नियुक्ति के बावजूद भी यहां मरीजों को इलाज के बदले मौत की ओर धकेला जाता है।

दिनांक 5 मार्च को गौंछी गांव का उधम अपनी विकलांग पत्नी बबीता को जैसे तैसे करके रात करीब 9 बजे बी के अस्पताल पहुंचा। वह प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसे दाखिल कर के उसका प्रसव कराने की अपेक्षा वहां मौजूद स्टाफ़ ने उन्हें यह कह कर भगा दिया कि यह सिजेरियन केस है, सुबह आना जब लेडी डाक्टर यहां होंगी। उधम ने बहुत अनुनय विनय किया कि इस हालत में ले जाना व सुबह लाना बहुत कठिन है। इसके बावजूद दर्द से कराहती बबीता को स्टाफ़ ने बिस्तर से उठा कर बाहर खदेड़ दिया।

उधम जैसे तैसे पत्नी को लेकर घर चला गया। रात करीब एक बजे पुन: प्रसव पीड़ा अत्यधिक होने पर उधम ने सरकार द्वारा बहुप्रचारित एम्बुलेंस नम्बर 102 पर काफ़ी देर तक फ़ोन किया जो किसी ने उठाने तक की भी जरूरत नहीं समझी।

बीके में पड़े सरकारी भ्रष्टाचार के शिकार

इस विकट परिस्थिति में बबीता ने रात करीब एक बजे एक बच्ची को जन्म दे दिया। अस्पताल स्टाफ़ द्वारा बताया गया सिजेरियन केस बिना ही किसी ऑपरेशन के हो गया। हो तो गया लेकिन बच्चा उल्टा पैदा हुआ जिससे जच्चा-बच्चा दोनों खतरे की हालत में बने रहे।

विदित है कि सरकार करोड़ों रुपया विज्ञापनबाज़ी पर खर्च करके दिन-रात प्रचार करने में जुटी रहती है कि प्रसव घरों में न करा कर अस्पतालों में करायें। इसके लिये सरकार द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं व सेवाओं का खूब बढ़ा-चढ़ा कर बखान किया जाता है। इस काम के लिये एम्बुलेंस सेवा के फ़ोन नं. 102 का भी विशेष उल्लेख किया जाता है। लेकिन वास्तविकता इसके एकदम विपरीत है। उधम-बबीता वाला उक्त केस कोई इक्का-दुक्का होने वाला अपवाद नहीं है। इस तरह के मामले यहां आये दिन होते हैं।

शेष पेज 2 पर

## ट्रैक्टर ट्रॉली से बस टकराई 4 घायल

# पुलिस की रिश्वतखोरी का सड़क पर धमाल

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** दिनांक 2-3 मार्च की रात को राजस्थान रोडवेज की बस जो मथुरा की ओर से दिल्ली को जा रही थी। झाड़सेतली गांव के निकट सड़क पर खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गयी जो सीमेंट की ईंटों से लदी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली पलट गयी व राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो गया, जिसे पुलिस एक घंटे की मशक्कत के बाद चालू करा सकी। इस दुर्घटना में बस ड्राइवर की टांग टूट गयी व बस में बैठी 3 महिलायें घायल हो गयी।

ट्रैक्टर मालिक शहर की इन्दिरा कॉलोनी रहने वाला है वह इसके द्वारा माल ढोने का काम करता है। उस रात वह बाहमणी खेड़ा के निकट स्थित एक फ़ैक्ट्री से राखी व सीमेंट से बनी ईंटे लाद कर फ़रीदाबाद की ओर आ रहा था कि उसका ट्रैक्टर खराब हो गया तो उसे वहीं सड़क पर खड़ा छोड़ कर वह अपने घर आ कर सो गया, यह सोच कर कि सुबह मिस्त्री ले जा कर ट्रैक्टर ठीक करा लेगा।

**करीब 2 वर्ष पूर्व 'मज़दूर मोर्चा' द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार शहर में चलने वाले 1200 ट्रैक्टर ट्राले ट्रैफ़िक पुलिस को एक हज़ार मासिक देते थे। इनके अलावा जो ट्रैक्टर चलते हैं वे जगह-जगह बने पुलिस नाकों पर बाकायदा 'इन्ट्री' देते हैं जो 50 रुपया से 100 रुपया तक हो सकती है।**

विदित है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से ले कर शहर की भीतरी सड़कों पर रात दिन हज़ारों ट्रैक्टर बड़ी ही बेढंगी बनी ट्रॉलियों को बेढंगे तरीके से लाद कर बेखौफ़ हो कर सड़कों पर दौड़ते हैं। किसी के सरिये गाटर, छड़ें बाहर निकल कर दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं तो ईंटों पत्थरों से लदी टॉलियां एक दूसरे से रेस लगती हुई सड़कों पर ईंट पत्थर बिखेर कर अन्य वाहनों के लिये मुसीबत पैदा करती हैं। इन ट्रैक्टरों के आगे पीछे कोई लाइट तो क्या रिफ़लेक्टर तक नहीं लगे होते। उक्त दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर की भी यही स्थिति थी। इसी के चलते रात के अंधेरे में बस चालक उस ट्राली को नहीं देख पाया था। शुक्र यह रहा कि यह टक्कर बस से हुई, यदि किसी कार या दुपहिया से हुई होती तो मौत निश्चित थी अभी पिछले दिनों बंचारी के निकट ऐसे ही एक हादसे में चार कार सवार मारे गये थे। दरअसल सड़कों पर बेखौफ़ दौड़ते ये ट्रैक्टर पूरी तरह से अवैध हैं। ये न तो सड़कों पर चलने के लिये फ़िट होते हैं और न ही इन्हें इसकी परमीशन होती है। कोई भी बीमा कम्पनी इनका बीमा नहीं करती। इसके बावजूद ये सड़कों पर पूरा आतंक मचाये रहते हैं। इन्हें किसी दुर्घटना का कोई भय नहीं होता क्योंकि इनका तो बिगरता कुछ नहीं और इनसे टकराने वाले का बचता कुछ नहीं।

शेष पेज 2 पर

## ख़बर दार

# राज्यपाल वांचू ने पाया इनाम वेस्टलैंड सौदे का

## सुरक्षा– सुविधा की आड़ में मापदंड बदले गये

वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटालों में इटली कनेक्शन के बावजूद, जैसी चुस्ती-फुर्ती दिखाई गयी है उससे यह भ्रम हो सकता है कि इस सौदे में इटली में जन्मी सोनिया गांधी का दूर दराज तक वास्ता नहीं हो सकता। अन्यथा उनके अपने पल्लू से बंधी कांग्रेस सरकार का रक्षा मंत्रालय इतनी तेज़ी से कार्यवाही करता नज़र नहीं आ सकता था आनन फ़ानन में इटली सरकार से विस्तृत जानकारी मांगने के लिये पत्र लिख दिया गया , हेलिकॉप्टर कम्पनी को करार रद्द करने के संकेत देने शुरू कर दिये गये, और जांच बढ़ाने के लिये सी बी आई द्वारा मुकदमा दर्ज करके तत्कालीन वायुसेनाध्यक्ष समेत अन्य बिचौलियों से पूछताछ शुरू हो गयी है।

क्या सचमुच कार्यवाही त्वरित रूप से हो रही है? घोटाले की ख़बर सत्ता एवं मीडिया के गलियारों में पिछले दो

राज्यपाल वांचू : सेवा का मेवा

वर्ष से घूम रही है। 'ईमानदार' रक्षामन्त्री ए के एनथोनी ने मामले को जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। केवल जब इटली से न्यायालय में उनके अपने कानूनों के तहत हेलिकॉप्टर कम्पनी द्वारा घूस दे कर सौदे लेने का मामला खुला तभी इस भारतीय सौदे की चर्चा भी उछली। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और तत्पश्चात राष्ट्रीय मीडिया द्वारा मामला संगीन रूप से उठाने के बाद एनथोनी और उनके रक्षा मन्त्रालय के पास कार्यवाही के नाम पर तुरन्त कुछ न कुछ करने का विकल्प ही बचा था। इटली सरकार ने जानकारी देने से फ़िलहाल मना कर दिया और सी बी आई तो अपने घर की है ही। लिहाजा इस ड्रामे को चलाते रहने में खतरा नहीं है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि घोटाले के दो हिस्से हैं। एक जो राजनीतिज्ञों की 'हां' पाने से सम्बन्धित है और दूसरा जो वायुसेना के नौकरशाहों एवं बिचौलियों को लेकर है। सारा शोर शराबा जो रक्षा मन्त्रालय कर रहा है और सारी जांच जो सी बी आई कर रही है वह दूसरे हिस्से तक सीमित है। पहले हिस्से तक जांच को लाने में इतने पेंच और इतना वक्त लगेगा कि कोई नतीजा निकलेगा ही नहीं। जगजाहिर है कि बड़े रक्षा सौदों में राजनीतिज्ञों का हिस्सा सबसे मोटा होता है। सवाल यह है कि एनथोनी की ईतमानदार छवि के चलते यह हिस्सा किसने डकारा? प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह की छवि भी ईमानदारी की है और जानकार हल्कों में कोई भी शायद ही माने कि वे ऐसे सौदे में साझेदारी करेंगे। तो बचा कौन? हाई कमांड यानी सोनिया गांधी परिवार, और इनके वफ़ादार मैनेजरों का टोला। कुछ संकेत पकड़ने मुश्किल नहीं हैं। बाजार भाव से बेहद महंगे वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के निर्णय के लिये आवश्यक काग़जों का पेट कैसे भर गया? क्योंकि बाज़ार में अपेक्षाकृत काफ़ी कम कीमत पर ऐसी ही गुणवत्ता वाले हेलीकॉप्टर मौजूद थे।

शेष पेज 2 पर